Winding up of SISI extension Centres at Tinsukia and Jorhat in Assam

*388. DR. NAGEN SAIKIA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued instructions to wind up the Small Industries Service Institute extension Centre and Field Testing Centre at Tinsukia and Jorhat in Assam;

(b) Whether it is a fact that winding up of these centres would affect the industrial development of the region;

(c) whether Government propose to review this decision ; and

(d) if not, what alternative steps are proposed to be taken for the benefits of the Small industries in the North-Eastern Region of the country ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) and (d) The needs of the North Eastern Region with regard to services and technical guidance will be met through main Institutes and their Branch institutes located in the region.

Non-verification of actual import cost and actual Consumption norms for imported raw material

*389. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY :

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the answer to unstarred question 1314 given in Rajya Sabha on 5th December, 1991 and state :

(a) whether it is a fact that non-verification of the actual import cost and actual consumption norms of imported raw material led to take increases in prices of over 70 bulk drugs ;

(b) whether it is a fact that as a result prices of over 50 per cent of the price controlled formulations have been raised;

(c) whether it is a fact that increases in prices of all anti-TB drugs, anti-amoebics, anti-inflammatory and other drugs were unjustified ; and

(d) whether Government would appoint a committee of the House to go into the whole affair and identify the persons behind this scandal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN) : (a) Sir, the prices of 55 bulk drugs using imported raw materials have been revised by the Government due to change in exchange rate of rupee against major foreign currencies last year on the basis of cost data available with the Government and in consultation with the BICP, as per the provisions of DPCO, 1987.

(b) No, Sir.

(c) No Sir. The increases in prices were related to the rise in input costs and were fully justified.

(d) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में बंद पड़े औद्योगिक एकक

*390. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कौन कौन से औद्योगिक एकक किन किन स्थानों पर बंद पड़े हुए हैं ;

(ख) ये कब से बंद पड़े हैं और इनके बंद होने के क्या कारण हैं ;

(ग) इन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ;

(घ) इन एककों को कब तक पुनः चालू कर दिये जाने की संभावना है ; और

(ङ) इन एककों के बंद होने से कितने कर्मकार बेरोजगार हो गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, सितंबर, 1990 के अंत में गैर लघु क्षेत्र में 60 रुग्ण एकक बंद पड़े थे। ऐसे एककों की जिला-वार संख्या अनुबंध में दी गई है । इन एकको के बंद होने की तारीख 1970 से 1989 के बीच है ।

बैंक द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार एकक बंद होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं ;

(1) तकनीकी समस्याएं (2) कच्चे माल की अनुपलब्धता (3) श्रम संबंधी समस्याएं (4) बिजली की कमी (5) प्राकृतिक विपत्ति, (6) परिवहन संबंधी रुकावटें तथा (7) वित्तीय बाधाएं ।

(ग) सितंबर, 1990 के अंत की स्थिति के अनुसार, गैर लघु क्षेत्र में 60 रुग्ण एककों में से, 4 एककों को उपचार कार्यक्रम के तहत रखा गया था ।

(घ) इन जीव्यक्षम एककों को पुनः चालू करने की कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती ।

(ङ) केन्द्र द्वारा ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

अनुबंध

उत्तर प्रदेश में बंद पड़े एककों का जिले-वार वर्गीकरण

जिले का नाम	बंद पड़े एककों की संख्या
1	2
आगरा	1
इलाहाबाद	2
अलीगढ़	3
अल्मोड़ा	1
बरेली	2
बस्ती	1
बुलन्दशहर	3
देहरादून	2
फैजाबाद	1
गाजियाबाद	18
गाजीपुर	1
कानपुर	4
लखनऊ	6
मथुरा	1
मुरादाबाद	2
पिथोरागढ़	1
राय बरेली	4
सुलतानपुर	1
टिहरी गढ़वाल	1
उन्नाव	4
वाराणसी	1
योग :	60

मितव्ययता संबंधी उपायों का विशेष भर्ती अभियान पर प्रभाव

*391. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के हाल के मितव्ययता अभियान के कारण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे के बकाया पदों को भरने हेतु चलाये जा रहे विशेष भर्ती अभियान पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस कोटे को एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भरने के लिए सरकारी विभागों/मंत्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति मरियम्मा आलेक्सा) : (क) किसी भी विभाग ने हमारे ध्यान में यह बात नहीं लायी है